पटना के उच्च न्यायालय में

1985 की सी.डब्लू.जे.सी. संख्या 1265

निर्णय लिया:02.05.1985

याचिकाकर्तागण: कृष्ण बल्लभ प्रसाद सिंह

बनाम

उत्तरदाता: उप-मंडल अधिकारी, हिल्सा-सह-वापसी अधिकारी और अन्य

भारत का संविधान-अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 329 (ख)-रिट आवेदन की रखरखाव-न्यायालय को अनुच्छेद 329 (b) और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 80 के अनुसार निर्वाचन अधिकारी के आदेश को चुनौती देने वाले अनुच्छेद 226 के तहत किसी भी आवेदन पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। (कंडिका-8)

भारत का संविधान-अनुच्छेद 327,328-संसद और राज्य विधानमंडल को संसद और राज्य विधानमंडल के चुनाव से संबंधित प्रावधान करने की शक्ति है-उच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 226 द्वारा ही लिया गया है।(कंडिका-9)

भारत का संविधान-अनुच्छेद 324 'चुनाव' शब्द का अर्थ व्यापक है-चुनाव का संचालन-अनुच्छेद 329 (ख) सहित भाग XV के अन्य प्रावधानों को सुसंगत रूप से पढ़े-चुनाव नामांकन दाखिल करने के साथ शुरू होता है और उम्मीदवार के निर्वाचित के बाद ही समाप्त होता है।(कंडिका-16)

रिट आवेदन संधार्य नहीं है-अंतिम चुनाव याचिका दायर करने के लिए याचिकाकर्ता का उपाय-रिट अदालत को याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई राहत प्रदान नहीं करनी चाहिए-रिट आवेदन विफल हो गया।(कंडिका-19,22)

पटना के उच्च न्यायालय में

1985 की सी.डब्लू.जे.सी. संख्या 1265

निर्णय लिया:02.05.1985

याचिकाकर्तागण: कृष्ण बल्लभ प्रसाद सिंह

बनाम

उत्तरदाता: उप-मंडल अधिकारी, हिल्सा-सह-वापसी अधिकारी और अन्य

माननीय न्यायाधीशगण/कोरम:

उदय सिन्हा, एल.एम. शर्मा और एच.एल. अग्रवाल, न्यायाधीशगण

निर्णय**एच.एल. अग्रवाल, न्यायाधीश**

1. यह रिट आवेदन, जो एक चुनाव मामले से उत्पन्न होता है, खंड पीठ के विद्वान न्यायाधीशों के बीच मतभेद के कारण मेरे सामने रखा गया है, जिनके सामने इसे मूल रूप से सुनवाई के लिए रखा गया था।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 329 (बी) में निहित प्रावधानों को देखते हुए रिट आवेदन के रख-रखाव के सवाल पर मतभेद उत्पन्न हुआ है।

2. मुख्य प्रश्न जो विचार के लिए आता है वह वह चरण है जिस पर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार के चुनाव की प्रक्रिया को भारत के संविधान के अनुच्छेद 329 (बी) के अर्थ के भीतर पूरा कहा जा सकता है।

3. जिन तथ्यों को मैं इसके बाद संक्षेप में बताऊंगा, वे कुछ को छोड़कर विवाद में नहीं हैं।

याचिकाकर्ता और प्रतिवादी संख्या 4 (रामस्वरूप प्रसाद), कई अन्य लोगों के अलावा, इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र (निर्वाचन क्षेत्र संख्या 197) से बिहार विधानसभा सीट के लिए चुनाव लड़ रहे थे। यह चुनाव मार्च, 1985 के महीने में हुआ था। याचिकाकर्ता ने कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया, जबकि प्रतिवादी संख्या 4 ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (1) पार्टी के उम्मीदवार के रूप में नामांकन पत्र दाखिल किया। उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र में मतदान 2 और 5 मार्च को हुआ था और मतों की गिनती 6 मार्च को की गई थी। गिनती के बाद पता चला कि 61 बूथों पर 90 प्रतिशत मतदान हो चुका है। याचिकाकर्ता द्वारा बूथ पर कब्जा करने के आरोप प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से लगाए गए थे। भारत के चुनाव आयोग ने तदनुसार केवल 60 केंद्रों पर फिर से मतदान करने का आदेश दिया। बूथ संख्या 60 नामक एक बूथ को, हालांकि, पुनर्मतदान में शामिल नहीं किया गया था क्योंकि इस स्टेशन पर वोटों को उम्मीदवारों द्वारा उचित अनुपात में साझा किया गया था।

4. तदनुसार पुनः मतदान 12-3-85 पर आयोजित किया गया था और गिनती के बाद, याचिकाकर्ता को बहुमत मत प्राप्त हुए, अर्थात्, 54,352 यानी, प्रतिवादी संख्या 4 से 274 मत अधिक। प्रत्यर्थी संख्या 4 ने मतपत्रों की पुनः गिनती के लिए एक आवेदन दायर किया लेकिन निर्वाचन अधिकारी ने आवेदन को अस्वीकार कर दिया और याचिकाकर्ता को विधानसभा के लिए विधिवत निर्वाचित होने की घोषणा की। निर्वाचन अधिकारी द्वारा उन्हें प्रपत्र संख्या 22 (अनुलग्नक 1) में चुनाव का प्रमाण पत्र भी दिया गया था। परिणाम की घोषणा आकाशवाणी द्वारा 13 मार्च की शाम को ही की गई थी और समाचार पत्रों ने 14 मार्च को खबर प्रकाशित की थी। तथ्य अभी तक विवाद में नहीं हैं।

निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी किए जाने के लिए आवश्यक प्रपत्र संख्या 2आईसी में प्रमाण पत्र, स्वीकार्य रूप से संबंधित प्राधिकारी को नहीं भेजा गया था। दूसरी ओर 15-3-85 को

निर्वाचन अधिकारी ने याचिकाकर्ता के चुनाव को रद्द करने और प्रतिवादी संख्या 4 को सफल उम्मीदवार घोषित करने के लिए दिनांकित 13-3-85 (अनुलग्नक 8) पर एक नोटिस जारी किया। निर्वाचन अधिकारी ने फॉर्म संख्या 21-सी और 22 में दिनांक 13-3-1985 वाला प्रमाण पत्र भी 15.03.1985 को (समय से पूर्व धटित होकर) जारी किया, जैसा कि याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है। प्रत्यर्थी संख्या 4 का नाम भी विधिवत निर्वाचित उम्मीदवार के रूप में सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया गया था।

5. याचिकाकर्ता की शिकायत है कि उसके चुनाव को रद्द करने के आदेश के साथ-साथ प्रतिवादी संख्या 4 के पक्ष में जारी प्रमाण पत्र (जवाबी हलफनामे के अनुलग्नक बी सहित), अधिकार क्षेत्र के बिना और पूरी तरह से अवैध होने के अलावा, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन के लिए भी दूषित है।

6. यह कहा जा सकता है कि इस नाटकीय परिवर्तन और विवादित आदेश के पारित होने का कारण बूथ संख्या 60 (एस. आई. सी.) के मतपत्रों की गिनती को छोड़ने में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा की गई गलती के कारण कहा जाता है, जिसमें याचिकाकर्ता को केवल 77 और प्रतिवादी संख्या 4,780 वोट मिले थे। इस प्रकार कहा जाता है कि प्रतिवादी संख्या 4 ने याचिकाकर्ता से 429 अधिक मत प्राप्त किए हैं।

7. प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा दायर जवाबी-हलफनामे में उन्होंने आरोप लगाया है कि याचिकाकर्ता ने उन पर फॉर्म संख्या 21 सी और 21 ई को भरने के पूरा होने से पहले ही प्रमाण पत्र (अनुलग्नक 1) देने के लिए दबाव डाला था, जो प्रक्रिया में थे और याचिकाकर्ता को उनके द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र गलती से हुआ था। जिस क्षण बूथ संख्या 60 के मतपत्रों की गिनती में चूक के संबंध में सहायक निर्वाचन अधिकारियों की रिपोर्ट में गलती का पता चला, मतों का फिर से मिलान किया गया और प्रतिवादी संख्या 4 को याचिकाकर्ता की तुलना में अधिक मत प्राप्त हुए। और तदनुसार उन्होंने गलती को ठीक किया और

याचिकाकर्ता के पक्ष में दिए गए प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया और प्रतिवादी संख्या 4 को विधिवत निर्वाचित उम्मीदवार घोषित किया और उनके पक्ष में आवश्यक प्रमाण पत्र जारी किए। याचिकाकर्ता ने तदनुसार उपरोक्त आदेशों को रद्द करने के लिए वर्तमान रिट आवेदन दायर किया है।

8. प्रत्यर्थियों का मुख्य रुख यह है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 329 (बी) में निहित बाधा को देखते हुए, इस न्यायालय को निर्वाचन अधिकारी के आदेश को चुनौती देने वाले अनुच्छेद 226 के तहत किसी भी आवेदन पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। अनुच्छेद 329 (बी) इस प्रकार है:

संसद के किसी भी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन के लिए कोई भी चुनाव प्रश्नगत नहीं बुलाया जाएगा, सिवाय उस चुनाव याचिका के जो ऐसे प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की गई हो और उस तरीके से जो उपयुक्त विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी कानून द्वारा या उसके तहत प्रदान की जाए।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (संक्षेप में "अधिनियम") की धारा 80 में भी इसी तरह का प्रावधान है, अर्थात् "चुनाव याचिका के अलावा किसी भी चुनाव को प्रश्नगत नहीं उठाया जाएगा"।

दोनों चुनाव लड़ने वाले दलों ने अपने-अपने मामलों के समर्थन में अनुच्छेद 329 (बी) को लागू किया है, लेकिन उनके रुख के बीच मुख्य अंतर यह है कि याचिकाकर्ता के अनुसार मतों की गिनती और याचिकाकर्ता को सफल उम्मीदवार घोषित करने के तुरंत बाद चुनाव प्रक्रिया समाप्त हो गई; उत्तरदाताओं के अनुसार, चुनाव प्रक्रिया फॉर्म 21 सी और 22 में प्रमाण पत्र जारी करने तक जारी रही। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील के अनुसार, निर्वाचन अधिकारी द्वारा पाई गई कथित गलतियों को उनके द्वारा ठीक नहीं किया जा सका क्योंकि वह मतों की गिनती और उसके परिणाम की घोषणा के बाद अधिकारहीन व्यक्ति बन गए

थे, और प्रतिवादी संख्या 4 का उपाय केवल एक नियमित चुनाव याचिका द्वारा याचिकाकर्ता के चुनाव को चुनौती देना था। पक्षों के बीच इस विवाद के लिए अधिनियम के कुछ प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के संदर्भ की आवश्यकता होती है।

9. संविधान के भाग XV में चुनावों से संबंधित प्रावधान हैं। अनुच्छेद 327 संसद को संसद या राज्य विधानमंडल के चुनावों से संबंधित या उनके संबंध में सभी मामलों के संबंध में कानून द्वारा प्रावधान करने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 328 राज्य विधानमंडलों को राज्य विधानमंडलों के चुनावों से संबंधित या उनके संबंध में सभी मामलों के संबंध में कानून द्वारा प्रावधान करने का अधिकार देता है, जहां तक कि संसद द्वारा उस संबंध में प्रावधान नहीं किया गया है और संविधान के प्रावधानों के अधीन है।

संविधान के अनुच्छेद 329 को अधिनियमित करने का उद्देश्य स्पष्ट रूप से उस अनुच्छेद में उल्लिखित मामलों के संबंध में न्यायालयों की अधिकारिता को बाहर करना है।

अधिनियम की धारा 105 और 170 या कोई अन्य प्रावधान किसी भी तरह से अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करने के लिए उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को प्रभावित नहीं कर सकते हैं। हालाँकि, इस अधिकार क्षेत्र को अधिनियम द्वारा नहीं बल्कि अनुच्छेद 226 द्वारा ही छीन लिया गया है।

अधिनियम का भाग 5 चुनाव के संचालन से संबंधित है, जो, जैसा कि सर्वविदित है, चुनाव के पहले समापन के साथ शुरू होता है, अर्थात् राष्ट्रपति द्वारा नोटिस जारी करके निर्वाचन क्षेत्र को चुनाव के लिए बुलाना। इस भाग को विभिन्न अध्यायों में विभाजित किया गया है और अध्याय V वर्तमान मामले के लिए प्रासंगिक अध्याय है जो मतों की गिनती (धारा 64) से शुरू होता है। धारा 66 में परिणामों की घोषणा का प्रावधान है और यह हमारे उद्देश्य के लिए सबसे अधिक प्रासंगिक है। बेहतर होगा कि मैं इसे उद्धृत करूं:

65. जब मतों की गिनती पूरी हो जाती है, तो निर्वाचन अधिकारी, चुनाव आयोग द्वारा इसके विपरीत किसी भी निर्देश के अभाव में, इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों द्वारा प्रदान की गई तरीके से चुनाव के परिणाम की घोषणा करेगा।

10. याचिकाकर्ता के वकील श्री गर्ग का पूरा तर्क धारा 66 के प्रावधानों पर आधारित था। उनका तर्क, जैसा कि पहले ही संकेत दिया जा चुका है, यह था कि मतों की गिनती पूरी होने के तुरंत बाद निर्वाचन अधिकारी को, इसके विपरीत निर्वाचन आयोग के निर्देश के अभाव में, चुनाव का परिणाम तुरंत घोषित करना होगा और जितना निर्वाचन अधिकारी ने याचिकाकर्ता के पक्ष में परिणाम घोषित किया है, चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने के कारण, निर्वाचन अधिकारी द्वारा एक मतदान केंद्र के मतों की फिर से गिनती करने या उन्हें जोड़ने में किए गए सभी बाद के कार्य, जिन्हें छोड़ दिया गया है, चुनाव प्रक्रिया से संबंधित कार्य नहीं हो सकते हैं। इसलिए याचिकाकर्ता निर्वाचन अधिकारी के उन कृत्यों को रद्द करने के लिए रिट आवेदन को बनाए रखने का हकदार था।

धारा 67 के अनुसार, चुनाव का परिणाम घोषित होने के बाद, निर्वाचन अधिकारी को उचित प्राधिकारी और चुनाव आयोग को और किसी राज्य के विधानमंडल के चुनाव की स्थिति में उस सदन के सचिव को भी इसकी सूचना देनी होती है, जो परिणाम को निर्वाचित उम्मीदवारों के नामों वाली घोषणाओं को सरकारी राजपत्र में प्रकाशित कराएगा।

श्री गर्ग के अनुसार, निर्वाचन अधिकारी द्वारा पहले से घोषित चुनाव के परिणाम को विभिन्न अधिकारियों को सूचित करने और उसके बाद के प्रकाशन के ये कार्य केवल मंत्रिस्तरीय कार्य थे और राजपत्र में परिणाम का प्रकाशन केवल घोषणा का एक प्रमाण था। विद्वान वकील ने सवाल उठाया कि क्या प्रकाशन सफल उम्मीदवार के वैध रूप से निर्वाचित सदस्य होने के अधिकार को छीन सकता है?

विद्वान वकील के तर्क में एक स्पष्ट भ्रांति है क्योंकि धारा 66 स्वयं चुनाव के परिणाम की घोषणा करने के तरीके को स्पष्ट रूप से निर्धारित करती है और वह तरीका "इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों द्वारा प्रदान किया गया है"। यह सर्वविदित सिद्धांत है कि यदि कोई आधिकारिक कार्य किसी भी निर्धारित तरीके से करने का प्रावधान है तो उसे उसी के अनुसार किया जाना चाहिए।

11. अब मैं चुनाव संचालन नियम, 1961 के कुछ नियमों का उल्लेख कर सकता हूँ। नियम 56 मतों की गिनती से संबंधित नियम है। इसका उप-नियम (7) इस प्रकार है:

मतदान केंद्र पर उपयोग किए जाने वाले सभी मतपेटियों में निहित सभी मतपत्रों की गिनती पूरी होने के बाद -

(ए) गणना पर्यवेक्षक फॉर्म 16 में गणना के परिणाम के भाग II को भरेगा और हस्ताक्षर करेगा, जिस पर निर्वाचन अधिकारी द्वारा भी हस्ताक्षर किए जाएंगे; और

(बी) निर्वाचन अधिकारी प्रपत्र 20 में परिणाम पत्रक में प्रविष्टियाँ करेगा और विवरणों की घोषणा करेगा।

12. निर्वाचन अधिकारी ने 13-3-1985 पर याचिकाकर्ता के पक्ष में घोषणा की थी कि सफल उम्मीदवार ने सबसे अधिक मतदान हासिल किया है, जो उनके विद्वान वकील के अनुसार, चुनाव की प्रक्रिया का अंतिम चरण था। श्री गर्ग के इस तर्क को उदय सिन्हा, न्यायाधीश ने भी स्वीकार कर लिया है, जहाँ यह कहा गया है कि घोषणा को घोषणा से भटकाया नहीं किया जा सकता है।

निस्संदेह यह सत्य कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के भाग्य का निर्धारण करने के लिए मतों की गिनती का परिणाम मुख्य मानदंड है और निर्वाचन अधिकारियों को बाद में किए

गए कार्य और औपचारिकताएं उक्त परिणाम के अनुरूप होनी चाहिए। सवाल यह है कि क्या कानून के क्षेत्र में जो चुनाव की प्रक्रिया को पूरा करेगा या तकनीकी रूप से चुनाव प्रक्रिया कुछ और औपचारिकताएं पूरी होने तक जारी रहेगी। इस संबंध में नियम 64 प्रासंगिक प्रतीत होता है जो इस प्रकार है:

64. चुनाव के परिणाम और चुनाव की वापसी की घोषणा। --निर्वाचन अधिकारी, धारा 65 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, यदि और जहाँ तक वे किसी विशेष मामले में लागू होते हैं, तो -

(ए) फॉर्म 21 सी या फॉर्म 21 डी में, जैसा भी उचित हो, घोषणा करें कि जिस उम्मीदवार को सबसे अधिक वैध वोट दिए गए हैं, वह धारा 66 के तहत निर्वाचित होगा और उसकी हस्ताक्षरित प्रतियां उपयुक्त प्राधिकारी, चुनाव आयोग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भेजें और

(बी) प्रपत्र 21 ई में चुनाव की वापसी को पूरा करें और प्रमाणित करें और उसकी हस्ताक्षरित प्रतियां चुनाव आयोग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भेजें।

13. विद्वत महाधिवक्ता के साथ-साथ प्रत्यर्थी संख्या 4 की ओर से उपस्थित श्री बलभद्र प्रसाद सिंह ने यह तर्क दिया कि चुनाव की प्रक्रिया परिणाम की घोषणा होने तक जारी रहती है और घोषणा करने का तरीका नियम 64 के तहत निर्धारित किया जाना चाहिए, अर्थात् विधानसभा क्षेत्र के मामले में प्रपत्र संख्या 21 सी में और चुनाव आयोग और अन्य अधिकारियों को प्रपत्र 21-ई में विवरणी प्रमाणित करना। इसके बाद भी नियम 66 के तहत प्रदान किए गए प्रपत्र संख्या 22 में "लौटे उम्मीदवार को चुनाव प्रमाण पत्र का अनुदान" भी आवश्यक था, जो निम्नानुसार है:

66. निर्वाचित उम्मीदवार को चुनाव प्रमाण-पत्र अनुदान करना। निर्वाचन अधिकारी द्वारा धारा 53 या धारा 66 के प्रावधानों के तहत किसी उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किए जाने के तुरंत बाद निर्वाचन अधिकारी ऐसे उम्मीदवार को प्रपत्र 22 में निर्वाचन का प्रमाण पत्र प्रदान करेगा और उम्मीदवार से उसके द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित रसीद की पावती प्राप्त करेगा और तुरंत लोक सभा के सचिव या, जैसा भी मामला हो, विधान सभा के सचिव को पंजीकृत डाक द्वारा पावती भेजेगा।

इन प्रावधानों पर यह तर्क दिया गया था कि जहां कानून द्वारा किसी काम को किसी विशेष तरीके से करने की आवश्यकता होती है, वहां यह माना जाएगा कि उस काम को किसी अन्य तरीके से करने पर प्रतिबंध लगाया गया है, देखें बिहार राज्य और एक अन्य बनाम ए.सी. सल्थाना और अन्य 1980 बी.एल.जे.आर. 18.

14. अधिनियम की धारा 79 (एफ) में दी गई 'लौटे हुए उम्मीदवार' की परिभाषा से कुछ मदद ली जा सकती है, जिसके अनुसार -

79. परिभाषाएँ।

XX XX XX

(एफ) 'लौटे हुए उम्मीदवार' का अर्थ है एक ऐसा उम्मीदवार जिसका नाम धारा 67 के तहत विधिवत निर्वाचित के रूप में प्रकाशित किया गया है।

श्री ब्रज किशोर प्रसाद जिन्होंने याचिकाकर्ता की ओर से उत्तर तर्क दिया, ने हालांकि प्रस्तुत किया कि इस परिभाषा का कोई सहारा नहीं लिया जा सकता है क्योंकि यह एक अलग भाग, अर्थात् भाग VI के तहत आता है, जो 'चुनावों के संबंध में विवादों' से निपटता है।

निस्संदेह यह सत्य कि यह परिभाषा अगले भाग में आती है जब चुनाव पूरा होने के बाद विवाद उठाए जाते हैं। धारा 81 किसी भी चुनाव प्रश्नगत उठाने वाली चुनाव याचिका की

प्रस्तुति से निपटने के दौरान, 'लौटे उम्मीदवार के चुनाव' की बात करती है। इसलिए, इस पद का उपयोग संसद द्वारा उस उम्मीदवार के संदर्भ में किया गया है जिसे पिछले भाग के तहत निर्वाचित घोषित किया गया है, और यह स्पष्ट करता है कि राजपत्र में सफल उम्मीदवार के नाम का प्रकाशन उसे 'वापस आया हुआ उम्मीदवार' बनाता है।

हम पहले ही देख चुके हैं कि नियम 64 और 66 में 'चुनाव की वापसी' और 'चुनाव से लौटे उम्मीदवार' अभिव्यक्ति का भी उपयोग किया गया है। इसलिए, धारा 79 के तहत परिभाषा को चुनाव की प्रक्रिया से असंबंधित नहीं कहा जा सकता है।

15. श्री गर्ग ने श्रीमती इंदिरा नेहरू गांधी बनाम श्री राज नारायण ए. आई. आर. 1975 एस. सी. 2229 और पैराग्राफ 320 से 326 विशेष रूप से, में मामले के कुछ अंशों का उल्लेख किया था, दिखाने के लिए कि कार्यकारी प्राधिकरण, अर्थात् इस मामले में निर्वाचन अधिकारी द्वारा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अपने कार्य के कथित निर्वहन में निर्णय लेने की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। श्री गर्ग के अनुसार, यदि याचिकाकर्ता के पक्ष में चुनाव के परिणाम की घोषणा करते समय निर्वाचन अधिकारी द्वारा कोई गलती की गई थी, तो उनके पास अपनी गलती को सुधारने और शक्ति या चुनाव न्यायाधिकरण को हड़पने की कोई शक्ति या कानून की मंजूरी नहीं थी।

श्री गर्ग की प्रस्तुतियाँ उनके मुख्य निवेदन के साथ सह-संबंधित हैं कि चुनाव की प्रक्रिया वोटों की गिनती और उसके परिणाम का पता लगाने पर आई थी।

निर्वाचन अधिकारी के मामले के अनुसार, उन्होंने एक महत्वपूर्ण गलती की थी और इसलिए, जब तक कि किसी भी उम्मीदवार को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार वापस नहीं किया जाता, जैसा कि उनकी ओर से विद्वान महाधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तब तक उनके पास अपनी गलती को सुधारने का आवश्यक अधिकार था।

16. चुनाव लड़ने वाले दलों की ओर से उठाए गए तर्क की दलदली इस महत्वपूर्ण सवाल पर आधारित हैं कि क्या 'चुनाव' शब्द का संकीर्ण अर्थ दिया जाना चाहिए या इसका व्यापक अर्थ दिया जाना चाहिए। संकीर्ण अर्थों में इसका अर्थ चुनाव के परिणाम के आधार पर उम्मीदवार का अंतिम चयन हो सकता है; व्यापक अर्थों में इस शब्द का उपयोग पूरी प्रक्रिया को संदर्भित करने के लिए किया जाता है जो एक निर्वाचित घोषित उम्मीदवार में समाप्त होता है। यही वह व्यापक अर्थ है जिसमें संविधान के भाग V में 'चुनाव' शब्द का उपयोग किया गया है। अनुच्छेद 324 में 'चुनाव का संचालन' अभिव्यक्ति का उपयोग, मेरे विचार में, विशेष रूप से उस व्यापक अर्थ की ओर इशारा करता है जिसे अनुच्छेद 329 (बी) सहित भाग XV में होने वाले अन्य प्रावधानों में लगातार पढ़ा जा सकता है। चुनाव तब शुरू होता है जब निर्वाचन अधिकारी के समक्ष नामांकन पत्र दाखिल किया जाता है और उम्मीदवार के लौटने के बाद ही इसे समाप्त माना जाना चाहिए। यह एक संपूर्ण निरंतर अभिन्न कार्यवाही है और इसका हर चरण चुनाव का एक हिस्सा है।

में पृष्ठ 347, चौथे संस्करण के कंडिका 642 का भी उल्लेख कर सकता हूँ, जो "लड़े गए संसदीय चुनाव में परिणाम की घोषणा" से संबंधित हैल्सबरीज़ लॉज़ ऑफ़ इंग्लैंड के खंड 15 से है। इसमें लिखा है:

642. लड़े गए संसदीय चुनाव में परिणाम की घोषणा। --एक लड़े गए संसदीय चुनाव में, जब चुनाव का परिणाम सुनिश्चित हो जाता है, तो निर्वाचन अधिकारी को तुरंत उस उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित करना चाहिए जिसे अधिकांश वोट दिए गए हैं, अपना नाम वयस्क क्लर्क को वापस करना चाहिए और अस्वीकृत मतपत्रों के बयान में दिखाए गए प्रत्येक शीर्ष के नीचे अस्वीकृत मतपत्रों की संख्या के साथ अपने नाम और प्रत्येक उम्मीदवार के लिए कुल वोटों की सार्वजनिक सूचना देनी चाहिए।

चागला, मुख्य न्यायाधीश शंकर नानासाहेब कर्पे बनाम निर्वाचन अधिकारी, कोलाबा जिला और एक अन्य। मुन/एम एच/0080/1952:AIR1952 वॉय 277 निम्नलिखित रूप में देखा गया:

.....हमारे दृढ़ संकल्प के लिए जो वास्तविक और महत्वपूर्ण सवाल उठता है, वह यह है कि अनुच्छेद 329 (बी) में उपयोग की गई अभिव्यक्ति 'चुनाव' पर हमें क्या व्याख्या करनी चाहिए। क्या 'चुनाव' का अर्थ है मतों की गिनती के परिणामस्वरूप चुनाव का परिणाम, या 'चुनाव' का व्यापक अर्थ है? हमारी राय में, अनुच्छेद 329 के संदर्भ में और अनुच्छेद 327 और 322 दोनों के साथ में और भाग XV में इसकी स्थापना में 'चुनाव' अभिव्यक्ति को पढ़ने से चुनाव के परिणाम या वोटों की गिनती के प्रत्येक सीमित अर्थ की तुलना में व्यापक अर्थ होना चाहिए। "चुनाव" का वही अर्थ है जो अनुच्छेद 327 और 328 में उपयोग की गई अभिव्यक्ति का है, अर्थात् चुनाव से संबंधित या उससे संबंधित मामले। "चुनाव" केवल अंतिम निर्णय या अंतिम परिणाम नहीं है। "चुनाव" अधिसूचना जारी होने से परिणाम घोषित होने तक का हर चरण है, और भले ही कोई चुनाव याचिका हो, चुनाव न्यायाधिकरण के निर्णय तक।

17. अब मैं उच्चतम न्यायालय के दो प्रसिद्ध फैसलों पर आता हूँ जिन्हें इस विषय पर भूमि चिह्न के रूप में सही वर्णित किया गया है, अर्थात् एन. पी. पोन्नुस्वामी बनाम निर्वाचन अधिकारी मनु/एस. सी./0049/1952:[1952]1 एस. सी. आर. 218 और मोहिंदर सिंह गिल बनाम मुख्य चुनाव आयुक्त मनु/एस. सी./0209/1977:[1978]2 एससीआर 272। पूर्व मामले में न्यायाधीश फजल अली ने न्यायालय की ओर से बोलते हुए कहा कि "चुनाव के लिए उम्मीदवार के रूप में मतदान करने या खड़े होने का अधिकार एक नागरिक अधिकार नहीं है, बल्कि यह कानून या विशेष कानून का एक हिस्सा है और यह उसके द्वारा लगाई गई सीमाओं के अधीन होना चाहिए और अपने सदस्यों के चुनाव से संबंधित सभी मामलों

की जांच और निर्धारण करना विधानमंडल का एकमात्र अधिकार है और यदि विधानमंडल इसे अपने हाथों से लेता है और एक विशेष न्यायाधिकरण में पूरी तरह से नया और अज्ञात अधिकार क्षेत्र निहित करता है, तो विशेष अधिकार क्षेत्र का प्रयोग उस कानून के अनुसार किया जाना चाहिए जो इसे बनाता है। "पृष्ठ 68 पर विद्वान न्यायाधीश ने आगे इस प्रकार टिप्पणी की:

मुझे ऐसा लगता है कि 'चुनाव' शब्द का उपयोग संविधान के भाग XV में व्यापक अर्थों में किया गया है, अर्थात्, किसी उम्मीदवार को विधायिका में वापस करने के लिए पूरी प्रक्रिया से गुजरने के लिए। अनुच्छेद 324 में 'चुनाव का संचालन' अभिव्यक्ति का उपयोग विशेष रूप से व्यापक अर्थ की ओर इशारा करता है, और उस अर्थ को अनुच्छेद 329 (बी) सहित भाग XV में पाए जाने वाले अन्य प्रावधानों में भी लगातार पढ़ा जा सकता है। जब भी हम किसी लोकतांत्रिक देश में चुनावों की बात करते हैं तो 'चुनाव' शब्द का इतना व्यापक अर्थ होता है, इस तथ्य से पता चलता है कि इस विषय पर लिखी गई अधिकांश पुस्तकों में और इस मामले से संबंधित कई मामलों में, एक सवाल यह है कि कब चुनाव शब्द 'चुनाव' का उपयोग पूरी प्रक्रिया के संदर्भ में किया जा सकता है और इसका उचित उपयोग किया गया है, जिसमें कई चरण होते हैं और कई कदम शामिल होते हैं, जिनमें से कुछ का प्रक्रिया के परिणाम पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।

पृष्ठ 69 पर फिर से यह देखा गया:

.....मुझे लगता है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों से यह कहना एक उचित निष्कर्ष होगा कि अधिनियम में केवल एक ही उपाय का प्रावधान है, वह उपाय चुनाव समाप्त होने के बाद एक चुनाव याचिका द्वारा प्रस्तुत किया जाना है, और किसी भी मध्यवर्ती चरण में कोई उपाय प्रदान नहीं किया गया है।

मोहिंदर सिंह गिल के मामले (ऊपर) में सर्वोच्च न्यायालय ने पोन्नुस्वामी के मामले में की गई विभिन्न टिप्पणियों का उल्लेख किया और जिनमें से सबसे प्रासंगिक, मेरे विचार में, प्रतिवदेन की कंडिका 26 में की गई निम्नलिखित टिप्पणी है:

संचालन का इंद्रधनुष, संक्षिप्त अभिव्यक्ति 'चुनाव' द्वारा कवर किया गया है, इस प्रकार प्रारंभिक अधिसूचना से शुरू होता है और एक उम्मीदवार की वापसी की घोषणा में समाप्त होता है।

और अंत में कंडिका 93 में यह कहा गया था:

हम यह कहते हुए निष्कर्ष निकालते हैं कि अनुच्छेद 329 (बी) की सीमा उतनी ही चौड़ी है जितनी धारा 98 के साथ पठित धारा 100 की सीमा।

18. उपरोक्त चर्चाओं से मुझे न्यायमूर्ति उदय सिन्हा के इस विचार से सहमत होना बेहद मुश्किल लगता है कि निर्वाचन अधिकारी को प्रत्यर्थी संख्या 4 को विधिवत निर्वाचित उम्मीदवार घोषित करने और सरकारी राजपत्र में प्रकाशन के लिए निर्धारित प्रपत्रों में अपना नाम वापस करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था और प्रत्यर्थी संख्या 4 के पक्ष में उक्त प्रकाशन एक शून्य है। हालाँकि, मैं कोई अन्य टिप्पणी करने से बचूंगा क्योंकि यदि याचिकाकर्ता चुनाव याचिका दायर कर सकता है, तो टिप्पणी अपने मामले की सुनवाई करने वाले विद्वान न्यायाधीश को शर्मिदा नहीं कर सकती है।

19. मैं न्यायमूर्ति शर्मा से सहमत हूँ कि रिट आवेदन विचारणीय नहीं है और याचिकाकर्ता का उपाय चुनाव याचिका दायर करना था और मामले के किसी भी दृष्टिकोण से, अभिलेख लाए गए तथ्यों को देखते हुए, इस न्यायालय को अपने रिट अधिकार क्षेत्र में याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई राहत नहीं देनी चाहिए। हालाँकि, मैं उनकी इस टिप्पणी से सहमत नहीं हूँ कि "इनमें से प्रत्येक उम्मीदवार एक चुनाव याचिका बनाए रखने का हकदार है" और मेरे

विचार में श्री बलभद्र प्रसाद सिंह द्वारा यह उचित रूप से प्रस्तुत किया गया है कि उनके मुवक्किल, प्रतिवादी संख्या 4, विधिवत वापस किए गए उम्मीदवार होने के नाते, किसी भी चुनाव याचिका दायर करने की आवश्यकता नहीं थी।

20. श्री गर्ग ने यह भी तर्क दिया था कि याचिकाकर्ता (अनुलग्नक 8) के परिणाम को रद्द करने और प्रतिवादी संख्या 4 के पक्ष में प्रमाण पत्र जारी करने पर प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन के कारण विचार किया गया था क्योंकि याचिकाकर्ता और उनके एजेंट और समर्थक परिणाम घोषित होने के बाद सभी वहां से चले गए थे।

मोहिंद्र सिंह गिल्ट के मामले में कंडिकाएँ 81 से 91 में टिप्पणियों के साथ यह तर्क पूरी तरह से पूरा हुआ है, जैसा कि विद्वान महाधिवक्ता द्वारा सही रूप से प्रस्तुत किया गया है; बल्कि, निम्नलिखित अवलोकन मामले को विवाद से परे बनाता है:

.....मामले को संदेह से परे रखने के लिए, प्राकृतिक न्याय जीवंत हो जाता है और पूर्ण पुनः मतदान के लिए विशिष्ट मामले या आदेश पर लागू होता है, हालांकि पूर्ण धूमधाम नहीं बल्कि लचीली व्यवहार्यता में। इसका अनुपालन किया गया है या नहीं, इसे न्यायाधिकरण के निर्णय के लिए खुला छोड़ दिया गया है।

मोहिंदर सिंह गिल (उपरोक्त) से निपटने वाले दिल्ली उच्च न्यायालय को भी इस प्रश्न से निपटने का अवसर मिला था और निम्नलिखित टिप्पणी इस प्रश्न के विपरीत है:

संसद और विधानसभाओं के लिए चुनाव कराने की योजना अधिनियम की धारा 73 के तहत अधिसूचना जारी करने के उद्देश्यों के लिए चुनावी प्रक्रिया के शीघ्र समापन के लिए निर्धारित समय-सारणी द्वारा शासित होती है। चुनाव में, भाग लेने वाले कई उम्मीदवारों के अलावा, सभी योग्य मतदाता जिन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, वे इसके उचित निष्कर्ष में उम्मीदवारों के साथ समानता में महत्वपूर्ण रूप

से रुचि रखते हैं। इसके अलावा चुनाव याचिका के माध्यम से एक स्थगित सुनवाई भी प्रदान की जाती है और परिणामों की घोषणा तक कोई निहित या नागरिक अधिकार शामिल नहीं होते हैं। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत विशेष रूप से प्रदान नहीं किए गए हैं, लेकिन वास्तव में विवादित आदेश पारित करते समय आवश्यक इरादे से पूरी तरह से बाहर हैं।

21. मैंने पर्याप्त कहा है और अब मुझे पोन्नुस्वामी के मामले से टिप्पणियों को उधार लेते हुए निष्कर्ष निकालना चाहिए और यह मानना चाहिए कि भारत में चुनाव का कानून इस बात पर विचार नहीं करता है कि चुनाव कार्यवाही से जुड़े मामलों पर दो हमले होने चाहिए, एक जब वे संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के असाधारण अधिकार क्षेत्र को लागू करके चल रहे हैं, और दूसरा जब वे तो एक चुनाव याचिका के माध्यम से पुरा हो गए हैं।

22. परिणामस्वरूप, एल. एम. शर्मा, न्यायमूर्ति के विचारों से सहमत होते हुए, मेरा मानना है कि यह आवेदन विफल होना चाहिए। तदनुसार इसे खारिज कर दिया जाता है, लेकिन मामले की विशिष्ट परिस्थितियों में, मैं पक्षों को उनकी लागत वहन करने के लिए छोड़ दूंगा।

खण्डन (डिस्क्लेमर):- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।